



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]  
No. 259]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 30, 2014/कार्तिक 8, 1936  
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2014/KARTIKA 8, 1936

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2014

### घरेलू प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण संबंधी नए दिशा-निर्देश, 2014

सं. 22013/27/2012-ओएनजी डीवी.—इस मंत्रालय की दिनांक 10.1.2014 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 22011/3/2012-ओएनजी डीवी के अधिक्रमण में, भारत सरकार एतद्वारा नए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश, 2014 को निम्नानुसार अधिसूचित करती है:—

1. इन दिशा-निर्देशों के तहत कूप शीर्ष गैस मूल्य \*(अनंतिम) नीचे दिए सूत्र के अनुसार निर्धारित किया जाएगा:—

$$\text{वीएचएच पीएचएच} + \text{वीएसी पीएसी} + \text{वीएनबीपी पीएनबीपी} + \text{वीआर पीआर}$$

$$\text{पी} = \frac{\text{वीएचएच} + \text{वीएसी} + \text{वीएनबीपी} + \text{वीआर}}{\text{पीएचएच} + \text{पीसी} + \text{पीनबीपी} + \text{पीआर}}$$

जहां

- वीएचएच = यूएसए और मैक्सिको में खपत की गई प्राकृतिक गैस की कुल वार्षिक मात्रा।
- वीएसी = कनाडा में खपत की गई प्राकृतिक गैस की कुल वार्षिक मात्रा।
- वीएनबीपी = रूस को छोड़कर, यूरोपीय संघ (ईयू) और पूर्व सोवियत संघ (एफएसयू) देशों में खपत की गई प्राकृतिक गैस की कुल वार्षिक मात्रा।
- वीआर = रूस में खपत की गई प्राकृतिक गैस की कुल वार्षिक मात्रा।

(v) पीएचएच और पीएनबीपी, हेनरी हब (एचएच) और नेशनल बेलेसिंग प्वाइंट (एनबीपी) में, पैरा 2 में दिए अनुसार दुलाई और उपचार प्रभारों को घटा कर, दैनिक मूल्यों की वार्षिक औसत है।

(vi) पीएससी और पीआर पैरा 2 में दिए अनुसार दुलाई और उपचार प्रभारों को घटा कर, अल्बर्टा हब और रूस में मासिक मूल्यों की वार्षिक औसत है (रूसी सरकार या समान स्रोत के फेडरल टैरिफ द्वारा यथा प्रकाशित)

(\*कूप शीर्ष मूल्य का संबंध गैस के क्रेता से संविदा क्षेत्र/पट्टा क्षेत्र में गैस उत्पादक द्वारा प्राप्त गैस के मूल्य से है। जमीनी ब्लॉकों के मामलों में, संविदा क्षेत्र में संविदाकार (उत्पादक) द्वारा प्राप्य मूल्य, कूप शीर्ष मूल्य होगा। अपतट ब्लॉकों के मामले में, यदि गैस अपतट संविदागत क्षेत्र में प्रसंस्कृत करके बेची जाती है, तो अपतट पर प्राप्य मूल्य कूप शीर्ष मूल्य होगा। यदि गैस प्रसंस्करण के लिए लैंड फाल स्थल पर लाई जाती है और लैंड फाल स्थल पर बेची जाती है, तो लैंड फाल स्थल में मौजूद सुविधाएं, संविदा क्षेत्र का भाग मानी जाएगी और लैंड फाल स्थल पर प्राप्य मूल्य कूप शीर्ष मूल्य होगा।)

2. तीनों विभिन्न हबों और रूस के लिए कूप शीर्ष मूल्य, प्रत्येक तीनों हब मूल्यों और रूसी मूल्य से दुलाई और उपचार प्रभारों के लिए अमरीकी डालर 0.50/एमएमबीटीयू घटा कर निर्धारित किया जाएगा।

3. इन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित गैस मूल्य, ओएनजीसी तथा ऑयल इंडिया को प्रदान किए गए नामांकन क्षेत्रों, नई अन्वेषण और लाइसेंस नीति (एनईएलपी) ब्लॉकों, जैसे एनईएलपी पूर्व ब्लॉक, जहां उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) में गैस मूल्यों के सरकारी अनुमोदन हेतु व्यवस्था है और नीचे पैरा 4 और 5 में यथा निर्दिष्ट को छोड़कर कोल बेड मिथेन (सीबीएम) ब्लॉकों से उत्पादित होने वाली सभी प्रकार की गैस पर लागू होगा।

4. इन दिशा-निर्देशों के तहत इस प्रकार निर्धारित गैस मूल्य किसी विशेष समयावधि के लिए संविदात्मक दृष्टि से निर्धारित मूल्यों पर तब तक लागू नहीं होगा, जब तक वह अवधि समाप्त नहीं हो जाती। यह गैस मूल्य उस स्थिति में भी लागू नहीं होगा जहां संबंधित पीएससी प्राकृतिक गैस मूल्य सूचीकरण/निर्धारण हेतु विशेष फार्मूले की दृष्टि से की गई है और जहां एनईएलपी-पूर्व पीएससीज में गैस मूल्यों के लिए फार्मूला/आधार के सरकारी अनुमोदन की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा, राष्ट्रीय तेल कंपनियों के नामांकन ब्लॉकों के छोटे/अलग-थलग क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण, इन क्षेत्रों के संबंध में 08 जुलाई, 2013 को जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के द्वारा ही नियंत्रित होता रहेगा।

5. ब्लॉक केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 की डी1, डी3 खोजों से परिकल्पित उत्पादन में कमी के कारण लागत निकासी से संबंधित मामला मध्यस्थाधीन है। इन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित मूल्य के बीच के अंतर को एनसीवी आधार पर परिवर्तित किया गया और वर्तमान मूल्य (4.2 अमरीकी डालर प्रति मिलियन बीटीयू) को गेल द्वारा रखे जाने वाले गैस पूल खाते में जमा कर दिया जाएगा और इस प्रकार एकत्रित की गई राशि क्या इन ब्लॉकों के संविदाकारों को देय है या नहीं, यह लंबित मध्यस्थता के संबंध में आने वाले निर्णय पर तथा संबंधित कानूनी कार्यवाहियों पर निर्भर करेगा।

6. मूल्य निर्धारण/अधिसूचना की आवधिकता अर्ध-वार्षिक होगी। इन दिशा-निर्देशों के तहत मूल्य का परिकलन करने के लिए प्रयुक्त मूल्य और मात्रा संबंधी आंकड़े एक तिमाही के अंतराल सहित पिछली चार तिमाहियों के होंगे। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में पूर्व वर्णित सूत्र के आधार पर प्रथम मूल्य, हेनरी हब, एनबीपी, अल्बर्टा कनाडा और रूस में 1 जुलाई, 2013 और 30 जून, 2014 के बीच प्रचलित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यह मूल्य 01 नवम्बर, 2014 से प्रभावी होगा और 31 मार्च, 2015 तक वैध रहेगा। इसके बाद, इसे 1 जनवरी, 2014 और 31 दिसम्बर, 2014 के बीच अर्थात् एक तिमाही के अंतराल के साथ इसी प्रकार प्रचलित उक्त मूल्यों के आधार पर 01 अप्रैल, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 की अवधि के लिए संशोधित किया जाएगा। इन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित मूल्य छः मास पहले घोषित किया जाएगा, जिसके लिए वह लागू है।

7. इन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित मूल्य 1 नवम्बर, 2014 से भावी रूप में लागू किया जाएगा।

8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन महानिदेशक, पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (डीजी, पीपीएसी), इन दिशा-निर्देशों के तहत मूल्यों के आवधिक संशोधन को अधिसूचित करेंगे।
9. इन दिशा-निर्देशों के जारी होने के बाद सभी खोजों के लिए, अत्यधिक गहरे समुद्री क्षेत्रों, गहरे समुद्री क्षेत्रों और उच्च दाब उच्च तापमान (कूप शीर्ष शट-इन प्रेशर > 690 बार्स, बॉटम होल तापमान > 150 डिग्री सेंटीग्रेड) क्षेत्रों में, पैरा 1 में दिए गए सूत्र के अनुसार निर्धारित गैस मूल्य पर प्रीमियम दिया जाएगा। इस पैरा के नीचे प्रीमियम निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
10. इन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित मूल्य जीसीवी के आधार पर होगा।
11. इन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित मूल्य अमरीकी डालर प्रति एमएमबीटीयू होगा।
12. पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में, ओएनजीसी/ओआईएल द्वारा आपूर्ति की जा रही गैस के लिए 40 प्रतिशत की राजसहायता उपलब्ध कराई जाती रहेगी। तथापि, चूंकि इस बात की संभावना है कि निजी प्रचालक भी एनईआर में गैस का उत्पादन शुरू करेंगे, और उसी बाजार में प्रचालन करेंगे, इसलिए अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, यह राजसहायता उनको भी उपलब्ध कराई जाएगी।
13. इन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित मूल्य सभी क्षेत्रों में एक समान रूप में लागू किया जाएगा।

उपेन्द्र प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2014

#### New Domestic Natural Gas Pricing Guidelines, 2014

**No. 22013/27/2012-ONG D.V.**—In supersession of this Ministry's Gazette notification No. 22011/3/2012-ONG.D.V., dated 10.1.2014, the Government of India hereby notifies the New Domestic Natural Gas Pricing Guidelines, 2014, as hereunder:—

1. The wellhead gas price\* (P), under these guidelines would be determined as per the formula given below:—

$$P = \frac{V_{HH} P_{HH} + V_{AC} P_{AC} + V_{NBP} P_{NBP} + V_R P_R}{V_{HH} + V_{AC} + V_{NBP} + V_R}$$

Where

- (i)  $V_{HH}$  = Total annual volume of natural gas consumed in USA & Mexico.
- (ii)  $V_{AC}$  = Total annual volume of natural gas consumed in Canada.
- (iii)  $V_{NBP}$  = Total annual volume of natural gas consumed in European Union (EU) and Former Soviet Union (FSU) countries, excluding Russia.
- (iv)  $V_R$  = Total annual volume of natural gas consumed in Russia.
- (v)  $P_{HH}$  and  $P_{NBP}$  are the annual average of daily prices at Henry Hub (HH) and National Balancing Point (NBP) respectively, less the transportation and treatment charges as given in para 2.
- (vi)  $P_{AC}$  and  $P_R$  are the annual average of monthly prices at Alberta Hub and Russia (as published by Federal Tariff of the Russian Government or equivalent source) respectively, less the transportation and treatment charges as given in para 2.

(\*Well head price refers to the price of gas receivable by the producer of gas at the contract area/lease area from the buyer of gas. In case of on-land blocks, the price receivable by the contractor (producer) in the contract area will be the well head price. In case of offshore blocks, if the gas is processed and sold in the offshore contract area, the price receivable at the offshore will be the well head price. If the gas is brought to landfall point for processing and is sold at landfall point, the facilities located in the landfall point will be considered part of the contract area and the price receivable at land fall point will be the well head price).

2. The wellhead price for three different hubs and Russia would be determined by deducting US \$ 0.50/MMBTU towards transportation and treatment charges from each of the three Hub prices and Russian price.
3. The gas price, determined, under these guidelines would be applicable to all gas produced from nomination fields given to ONGC and OIL India, New Exploration and Licensing Policy (NELP) blocks, such Pre-NELP blocks where, the Production Sharing Contract (PSC) provides for Government approval of gas prices and Coal Bed Methane (CBM) blocks except as indicated in para 4 and 5 below.
4. The gas price, so determined under these guidelines shall not be applicable, where prices have been fixed contractually for a certain period of time, till the end of such period. This gas price shall also not be applicable where the PSC concerned provides for a specific formula for natural gas price indexation/fixation and to such Pre-NELP PSCs which do not provide for Government approval of formula/basis for gas prices. Further, the pricing of natural gas from small/isolated fields in the nomination blocks of NOCs will continue to be governed by the extant guidelines in respect of these fields issued on 8th July, 2013.
5. The matter relating to cost recovery on account of shortfall in envisaged production from D1, D3 discoveries of Block KG-DWN-98/3 is under arbitration. The difference between the price, determined under these guidelines converted to NCV basis and the present price (US \$ 4.2 per million BTU) would be credited to the gas pool account maintained by GAIL and whether the amount so collected is payable or not, to the contractors of this Blocks, would be dependent on the outcome of the award of pending arbitration and any attendant legal proceedings.
6. The periodicity of price determination/notification shall be half yearly. The price and volume data used for calculation of price under these guidelines shall be the trailing four quarter data with one quarter lag. The first price on the basis of aforementioned formula in these guidelines would be determined on the basis of price prevailing at Henry Hub, NBP, Alberta Canada and Russia, between 1<sup>st</sup> July, 2013 and 30<sup>th</sup> June, 2014. This price would come into effect from 1<sup>st</sup> November, 2014 and would remain valid till 31<sup>st</sup> March, 2015. Thereafter, it would be revised for the period 1<sup>st</sup> April, 2015 to 30<sup>th</sup> September, 2015 on the basis of said prices prevalent between 1<sup>st</sup> January, 2014 and 31<sup>st</sup> December, 2014, i.e., with the lag of a quarter and so on. The price determined under these guidelines would be announced in advance of the half year, for which it is applicable.
7. The price determined under these guidelines would be applied prospectively with effect from 1<sup>st</sup> November, 2014.
8. Director General of Petroleum Planning and Analysis Cell (DG PPAC) under the Ministry of Petroleum and Natural Gas shall notify the periodic revision of prices under these guidelines.
9. For all discoveries after the issuance of these guidelines, in Ultra Deep Water Areas, Deep Water Areas and High Pressure High Temperature (well head shut-in pressure > 690 bars, bottom hole temperature > 150 degree centigrade) areas, a premium would be given on the gas price determined as per the formula given in para 1. The premium under this para shall be determined as per prescribed procedure.
10. Price determined under these guidelines would be on GCV basis.
11. The price, determined under these guidelines would be in US \$ per MMBTU.
12. In the North Eastern Region (NER), the 40% subsidy would continue to be available for gas supplied by ONGC/OIL. However, as private operators are also likely to start production of gas in NER, and would be operating in the same market, this subsidy would also be available to them to incentivize exploration and production.
13. The price determined under these guidelines shall be applicable to all sectors uniformly.

UPENDRA PRASAD SINGH, Jt. Secy.